



**Jews Can Defend Themselves**

The big change in the world for Jews has been the fact that Jews are no longer unable to defend themselves. For 2,000 years, Jews were always a minority.

**Candy Leaf from Assam**

**Happy Da Dhabha @ Monarch**

# यू.ए.ई. ने राजस्थान के साथ तीन लाख करोड़ का एम.ओ.यू. किया

**मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यू.ए.ई. के निवेश मंत्री सुवैदी ने 60 गीगावॉट की सोलर, विंड व हाइब्रिड परियोजना फाइनल की**

जयपुर, 22 अक्टूबर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एम.ओ.यू. पर मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावॉट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए

आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए, एक दीर्घ अवधि की विद्युत परियोजना की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। इस पहल के अंतर्गत यू.ए.ई. एक योग्य एवं सक्षम डेवलपर की नियुक्ति भी करेगा, जो प्रदेश में शासन-प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से साकार रूप प्रदान करेगा।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी की उपस्थिति में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए।

■ इस परियोजना में अक्षय ऊर्जा से संबंधित आधुनिकतम तकनीक के उपयोग से दीर्घ अवधि विद्युत परियोजना स्थापित की जायेगी। यू.ए.ई. एक योग्य व सक्षम डेवलपर नियुक्त करेगा जो राजस्थान में शासन व प्रशासन के स्तर पर समन्वय स्थापित रखेगा।

■ संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सरकारी फंड से तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।

किया जाएगा।

यू.ए.ई. के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक एम.ओ.यू. अक्षय ऊर्जा से संबंधित

मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान समिटि के तहत किए जा रहे प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में निवेश की विश्वसनीयता बढ़ी है। समिटि के तहत, अब तक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा था। लेकिन अब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच हुआ सीटों का बंटवारा

**बजरंग पुनिया किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने**

**जे.एम.एम. 41, कांग्रेस 29, राजद 9 और वामपंथी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी**

श्रीनंद झा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। झारखण्ड में इण्डिया ब्लाक का प्रमुख सहयोगी दल, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) मुश्किल का सामना कर रहा है, क्योंकि, उसके गठबंधन पार्टनर सामर्थ्य से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि, राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें जे.एम.एम. के लिए 41 सीटें, कांग्रेस के लिए 29, आर.जे.डी. के लिए 9 तथा सी.पी.आई.एम.एल. के लिए 2 सीटें हैं। जे.एम.एम. ने 50 सीटों की अपनी पूर्व की मांग को कम कर दिया है, लेकिन लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

आर.जे.डी. के मनोज झा के इस कथन से भारी वाद विवाद छिड़ गया कि

■ जे.एम.एम. पहले 50 सीटों पर लड़ने वाली थी पर सहयोगी दलों को एडजस्ट करने के लिए उसने 41 सीटों पर संतोष कर लिया।

■ पर इससे भी कोई लाभ होता नहीं लग रहा, क्योंकि राजद के मनोज झा ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी 18 से कम सीटों पर नहीं मानेगी।

■ इंडिया गठबंधन की इस तकरार से निस्संदेह राज्य में भाजपा को फायदा होगा।

उनकी पार्टी 18 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यदि ऐसा हुआ तो इण्डिया ब्लाक का सीट शेयरिंग फार्मुला ठप हो जाएगा।

पूर्व में योजना यह थी कि जे.एम.एम. 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तथा वाम पार्टियों को अपने कोटा में एडजस्ट करेगा और कांग्रेस, 31 सीटों

जाल खंबाता - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। पहलवान बजरंग पुनिया, जो हरियाणा विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए थे, को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है यह जानकारी किसान कांग्रेस के

ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में यह घोषणा की। अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए दी। इस दौरान ए.आई.सी.सी. महासचिव कुमारी सैलजा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह और विनेश फोगाट भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पुनिया व विनेश का फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया गया। खैरा ने कहा कि पुनिया किसानों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# उपभोक्ता आयोग ने आई.सी.आई.सी. आई. बैंक की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिये

जयपुर, 22 अक्टूबर जिला उपभोक्ता आयोग, क्रम-4 ने आयोग के आदेश के बावजूद, परिवारी को बीमा क्लेम के 9.50 लाख रुपए का ब्याज सहित भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने विपक्षी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

परिवारी को बीमा क्लेम की 9.50 लाख रुपये की राशि मय ब्याज अदा करने के अदालती आदेश की क्रियान्विति नहीं करने के कारण अहिंसा सार्किल स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिये गये।

को अहिंसा सार्किल, सी-स्क्रीम स्थित चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने ज्युल कलेक्टर को वसूली के लिए पत्रावली भेजने को कहा है। आयोग ने यह आदेश बंदना बोहरा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. सतीश मिश्रा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। महाराष्ट्र के आसन्न विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस और शिव सेना (यू.बी.टी.) के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर गतिरोध बना हुआ है तथा भाजपा इसका फायदा उठा रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन-समर्थक कुछ समाचार चैनल कांग्रेस सूत्रों का हवाला देते हुये ऐसी अफवाहें प्रचलित-प्रसारित कर रहे हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा शिव सेना प्रवक्ता संजय राउत के बीच कोई मीटिंग हुई है। जहाँ राउत ने ऐसी किसी भी मीटिंग का खंडन किया है, लेकिन ये समाचार चैनल बड़े दावे के साथ जनता में सन्देह पैदा करने में लगे हुये हैं। इस बीच, आसन्न महाराष्ट्र चुनावों के

# शिवसेना-कांग्रेस सीट बंटवारे में देरी से अफवाहें फैलीं

**महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के नजदीकी न्यूज चैनलों ने उक्त अफवाहों को हवा दी**

एक "अफवाह" के अनुसार केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के बीच बैठक हुई। संजय राउत ने ऐसी किसी भी बैठक से इन्कार किया, पर न्यूज चैनल बाद में भी बैठक की न्यूज ही चलाते रहे।

शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने उत्साह के साथ कहा कि सीटों का गतिरोध जल्दी खत्म हो जाएगा। विवाद वाली सीटें अधिक नहीं हैं। हम जल्द ही उन्हें निपटा लेंगे।

लिये सीट-शेयरिंग को लेकर महा विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) के अन्दरूनी मतभेदों का समाधान करने की कोशिश के तहत, राज्य के कांग्रेस नेताओं ने आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.-एस.सी.पी.) प्रमुख शरद पवार के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने आशावादी स्वर में

# जे.पी.सी. की बैठक में बोलत फेंकी गई अध्यक्ष पर

नेपु मिन्तल-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। वक्फ बोर्ड के सम्बन्ध में मंगलवार को जे.पी.सी. की मीटिंग गर्मा-गर्मी तथा आक्रोश की स्थिति तक पहुँच गई। उत्तेजनापूर्ण स्थिति में पहुँच गई मीटिंग में वस्तुतः खून भी बहा, बोलतें भी टूटीं, तू-तू मैं-मैं भी हुई तथा एक सांसद निलम्बित भी कर दिये गये। टी.एम.सी. सांसद कल्याण बनर्जी जे.पी.सी. की अगली मीटिंग से निलम्बित कर दिये गये हैं क्योंकि उन्होंने

वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर गठित जे.पी.सी. की मीटिंग के दौरान तुणमूल सांसद कल्याण बनर्जी काफी उग्र हो गए और उन्होंने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर बोलत फेंक दी। कल्याण बनर्जी को निलम्बित कर दिया गया है।

जे.पी.सी. के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर काँच की बोलत तक फेंक दी। ऐसा करने में कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लग गई तथा खून बहने लगा। दरअसल, पश्चिम बंगाल के एक भाजपा सांसद के साथ बनर्जी की उत्तेजनापूर्ण बहस हो गई थी, जिसके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# ब्रिक्स सम्मेलन में भारत छाया रहा

**हालांकि चीन ने सम्मेलन को अमेरिका एवं पश्चिमी देश विरोधी बनाने की कोशिश की पर भारत एवं रूस ने ऐसा नहीं होने दिया**

अंजन राय - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। रूस के कजाख शहर में आयोजित ब्रिक्स समिटि को रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन द्वारा सबसे बड़े राजनयिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। गत वर्ष, पुतिन ब्रिक्स मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया हुआ था। प्रारंभ से ही ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन्स के सदस्य के रूप में भारत का इसमें अग्रणी स्थान रहा है तथा जब कई देश, एक प्रमुख कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत को पूर्ण कूटनीतिक समर्थन प्राप्त था। यू.एस. तथा कैनडा, दोनों ही सिख अलगाववादी की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगाकर भारत को परेशान कर रहे थे।

रूस अभी उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका में ट्रम्प जीतकर आयेगे। इसके बाद ट्रम्प से दोस्ती अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूस को उसका उचित स्थान दिलाएगी। भारत के बढ़ते रूतबे ने भारत विरोधी देशों, कैनडा आदि को भी अपना राग बदलने को मजबूर कर दिया है।

जहाँ, एक तरफ चीन के शी जिन्पिंग ब्रिक्स के सम्मेलन को, अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश करना चाहते हैं, वहीं, पुतिन इसे "पश्चिम विरोधी गठबंधन" के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि निकट भविष्य में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से दो सप्ताह पहले पुतिन, डॉनल्ड ट्रम्प की जीत की उम्मीद को जीवित रखें हैं। यदि ऐसा होता है तो, पश्चिम में कई लोगों का मानना है कि, ब्लादिमिर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे होंगे। यदि ट्रम्प जीतते हैं तो पुतिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी को विश्वास है कि चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा, अमेरिका हमेशा की तरह अपना चीन विरोधी कार्ड खेलना जारी रखेगा। अतः चीन के राष्ट्रपति एक पूर्ण पश्चिम विरोधी गठबंधन पर जोर दे रहे हैं, जिसका नेतृत्व शी करना चाहते हैं।

# सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को केन्द्र सरकार ने क्लीन चिट दी

**सरकारी सूत्रों ने कहा कि जांच में माधवी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला**

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिये हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को जाँच-पड़ताल में उनके या उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, तथा इसलिये उनके खिलाफ किसी कार्यवाही की योजना नहीं है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि सेबी प्रमुख अपना कार्यकाल पूरा करेंगी।

सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टी.वी. को बताया कि सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस.ई.बी.आई.-सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर लगाये गये आरोपों की जाँच-पड़ताल में कुछ भी दोषपूर्ण नहीं पाया गया है। सूत्रों ने कहा कि फरवरी, 2025 में समाप्त होने वाला अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। सूत्रों ने कहा कि जाँच कराय जाना तो इसलिये आवश्यक हो गया था,

सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि माधवी पर किसी भी किस्म की कार्यवाही की योजना नहीं है, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, जो फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। सेबी चीफ पर अमेरिकन शॉर्ट सैलर हिंडन बर्ग ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, इसके बाद कांग्रेस ने माधवी बुच व उनके पति पर हितों के टकराव और वित्तीय दूरचरण तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

क्योंकि अमेरिकन शॉर्ट-सैलर हिंडनबर्ग रिसर्च तथा कांग्रेस पार्टी ने सेबी-प्रमुख के खिलाफ हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) एवं वित्तीय दूरचरण के गम्भीर आरोप लगाये थे। सूत्रों ने कहा कि एजेंसियों से उक्त आरोपों की तह में जाने के लिये कहा गया था। इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय ने भी इस मामले की जाँच शुरू कर दी थी। कांग्रेस द्वारा लगाया गया एक

2007 में प्रस्तावित की गई थी तथा उस समय यू.पी.ए. की सत्ता थी। 2016 में, सेबी ने मानकों का सैट जारी किया था। बुच 1 मार्च 2022 को, अजय त्यागी के बाद, सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त हुई थीं। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टी.वी. को बताया कि जहाँ बुच को ऐसे महत्वपूर्ण सुधार लागू करने का श्रेय जाता है जिनसे "ब्लैक स्टोन" सहित, विभिन्न ग्लोबल प्लेयर्स प्रभावित हुये थे। सूत्रों ने बुच पर लगाये गये आरोपों को राजनीति-प्रेरित तथा आधारहीन बताया। बुच पर लगाया गया दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में अपनी पूर्ववर्ती सेवा से प्राप्त आय को उजागर नहीं किया। यह दावा किया गया था कि उन्होंने बैंक से प्राप्त धनराशि की जानकारी सही तरीके से नहीं दी थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्राथमिक आरोप यह था कि बुच द्वारा किये गये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आर.ई.आई.टी.) के प्रमोशन से एक वैश्विक निवेश फर्म "ब्लैकस्टोन" का लाभ पहुँचा था तथा इस फर्म से सेबी प्रमुख के पति जुड़े हुये थे। विपक्ष ने उन पर यह आरोप लगाया था कि सेबी चेयरपर्सन के रूप में, उन्होंने "ब्लैक स्टोन" को लाभ पहुँचाने के लिये अपने पद का दुरुपयोग किया था। लेकिन आर.ई.आई.टी. सर्व प्रथम

बुच पर लगाया गया दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में अपनी पूर्ववर्ती सेवा से प्राप्त आय को उजागर नहीं किया। यह दावा किया गया था कि उन्होंने बैंक से प्राप्त धनराशि की जानकारी सही तरीके से नहीं दी थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# केन्द्रीय गृह सचिव और सी.आर.पी. एफ. के डी.जी. को अवमानना नोटिस

जयपुर, 22 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सी.आर.पी.एफ. के डी.जी. अनिस दयाल सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि उनकी ओर से अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की अवमानना याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने के कारण अवमानना नोटिस जारी किये।

पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता एल.के. शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को सी.आर.पी.एफ. के सिपाही पद से हटा दिया गया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गत वर्ष 16 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ के साथ पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)